आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार

देहरादून (उत्तराखण्ड)

गुरुवार 04.09.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर जीएसटी घटाया, नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी।
- जीएसटी परिषद ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य करने पर सहमति जताई।
- कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
- मुख्य सचिव ने आपदा विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों में हेली सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए।
- रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मौसम में सुधार होने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू की।

जीएसटी दर में बदलाव

केंद्र सरकार ने आम जनता और मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने जीएसटी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए करों के बोझ को कम कर दिया है।

नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल दो श्रेणियों में कर दिया गया है और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुधार किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर करों की समीक्षा कर अधिकांश मामलों में बड़ी कटौती की गई है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

छोटे वाहनों और मोटरसाइकिलों पर कर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और तिपहिया वाहनों पर भी यही दर लागू होगी, जबकि सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है।

जीएसटी दर में बदलाव –2

स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत देते हुए 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कर को शून्य कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ये सभी बदलाव 22 सितंबर 2025, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों की सहमति से लिए गए इन निर्णयों से आम आदमी, किसान, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

समस्या

देहरादून स्थित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों की समस्याओं पर बैठक आयोजित हुई। इसमें पोर्टल पर चिकित्सकीय दरों में विसंगति, निरस्त व गलत चिकित्सा दावे, लंबित देयकों के भुगतान और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। प्राधिकरण स्तर की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविन्द सिंह ह्यांकी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने की। उन्होंने अस्पतालों से कहा कि आयुष्मान और राज्य स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के बेड उपलब्ध कराएं और समन्वय के साथ कार्य करें। अस्पतालों ने इस पर सहमति जताई।

अरविन्द सिंह ह्यांकी ने कहा कि प्राधिकरण स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि लाभार्थियों को जानबूझकर परेशान करने या बेड न देने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पतालों से योजना की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की अपील की।

एमडीडीए

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने चालंग गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 500 करोड़ रुपये के घोटाले की खबरों को भ्रामक और असत्य बताया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, इसलिए वित्तीय अनियमितता का सवाल ही नहीं उठता।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से ग्राम चालंग में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत नहीं की गई है और इस संबंध में फैलाई जा रही खबरें तथ्यहीन हैं। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह जनमानस को गुमराह करने वाली खबरें हैं।

प्राधिकरण ने बताया कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच निजी भू–स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी। यह मात्र एक निजी हाउसिंग मॉडल था, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का रूप देने का प्रयास किया गया।

प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए सीधे प्राधिकरण से संपर्क करें।

आकलन

प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में श्री जोशी ने उत्तरकाशी के धराली और आसपास के क्षेत्रों में शीघ्र अस्थायी स्टोरेज निर्माण कराने के साथ किसानों को समय पर फल, सब्जियों के बीज, मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने और एप्पल मिशन के तहत सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने कहा कि यदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग समय पर नहीं खुल पाया तो सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए एमएसपी का वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार रखा जाए। इसके अलावा सेब के ए और बी ग्रेड फलों की एमएसपी का प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार करने को कहा।

कार्यकारिणी समिति बैठक

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीआरएफ दल के प्रशिक्षण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की शेष धनराशि वर्तमान वर्ष में खर्च करने, चंपावत और पौड़ी जिलों को राहत, बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दूसरी किश्त जारी करने पर सहमति बनी।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव–वन्यजीव संघर्ष सहित आपदा प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान सहायता तुरंत वितरित की जाए और लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। आपदा विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों में हेली सेवाओं के लिए एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए गए।

श्री बर्द्धन ने देहरादून में रिस्पना नदी के चैनलाइजेशन और निकासी कार्यों के लिए सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग को संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही, प्रदेश की बड़ी नदियों का अध्ययन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना बनाने और बाढ़ प्रभावित बस्तियों के लिए सुरक्षा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

राहत सामग्री आपूर्ति वाया हेलीकॉप्टर

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मौसम में सुधार होने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री की आपूर्ति फिर शुरू कर दी है। साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत, बचाव और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार जारी हैं।

ग्राम पंचायत स्यूर के बकोला, स्यूर और बरसाल तोक में 60 प्रभावित परिवारों को राशन किट और 5 सोलर लाइटें वितरित की गईं। ग्राम प्रधान को आकस्मिक जरूरत के लिए 2 बड़े टेंट भी उपलब्ध कराए गए। तालजामण के थपौनी तोक में पेयजल आपूर्ति के लिए पीवीसी पाइप भेजे गए, जबकि खाट–किमाणा क्षेत्र में जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के तहत दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं, जखोली क्षेत्र में दो सुरक्षित प्रसव कराए गए।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि हर प्रभावित परिवार तक राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है।

भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने भेंट की। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान स्वरूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि दून विश्वविद्यालय का यह कदम शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि अन्य संस्थान भी इसी प्रकार आपदा राहत कार्यों में सहयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता से संचालित कर रही है और जन सहयोग से ये कार्य और प्रभावी हो सकेंगे।